Insofar as how we propagate environmental aspects and properties of jute, as I have said about geotextiles, when you talk about containing landslides, you try and use jute for stopping landslides. This is obviously a biodegradable element. It Will help in ensuring sustainability and growth of the industry. It will also ensure that efforts like building of roads do have an element of jute, thereby reducing the use of plastic. Thereby, we are complementing growth of industry and the environmental concerns as articulated by the hon. Member. But, Sir, traditionally, our jute mills are dependent on the packaging orders that they get from the Centre and States. Given that the Centre does, through FCI demands, have an order of close to ₹5,000 crore per year to sustain the industry, we additionally are writing to State Governments, especially, the State Government of Bengal requesting them that the paddy and rice that they procure, be compulsorily packaged in jute because it is a food item thereby increasing the capacity and generating an additional demand of 80,000 metric tonnes. We have also requested them that you package potatoes and other vegetables in jute hessian bags which will also, again, increase demand by 40,000 metric tonnes but also be environmentally very complementary to the vegetables and food articles we consume.

*321. **[The questioner was absent.]**

राज्य प्रतिनिधियों द्वारा रेल परियोजनाओं पर निगरानी रखा जाना

*321. **श्री महेन्द्र सिंह माहरा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों में चल रही परियोजनाओं पर निगरानी रखने हेतु राज्यों से प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में किन-किन राज्यों से प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए गए हैं और ऐसी नियुक्तियां कब तक कर दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां। रेल परियोजनाओं में तेजी लाने तथा इनके शीघ्र निष्पादन हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सुधार लाने के लिए, रेल मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया था। अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में रेल परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को आपसी समन्वय से निपटाने और प्रगति की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर दिए हैं।

सभी राज्यों के प्रतिनिधियों/नामितियों का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है (नीचे देखिए)। राज्यों के प्रतिनिधि/नामिति, रेल प्राधिकारियों के साथ संरेखण, भूमि अधिग्रहण, वन एव वन्य जीव क्लियरेंस, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं, ऊपरी और निचले सड़क पुलों, बिजली लाइनों की शिफ्टिंग, नहरों की क्रॉसिंग, परियोजनाओं का वित्तपोषण, इच्छुक पार्टियों की पहचान आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्रीय रेलवे से नोडल अधिकारियों को भी मनोनीत किया गया है, जिसमें परियोजनाओं की पहचान करने, राज्य सरकार के साथ अपेक्षित समन्वय स्थापित करने और राज्य सरकार के साथ रेलवे पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित करने के लिए उनकी भूमिका परिभाषित की गई है।

रेल मंत्रालय में उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान सूचना के आदान-प्रदान को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए भी रेलवे बोर्ड में नोडल अधिकारियों को मनोनीत किया गया है, जो रेलवे संबंधी विभिन्न परियोजनाओं तथा मामलों की प्रगति की निगरानी के बारे में अद्यतन स्थिति की जानकारी रखेंगे।

परिशिष्ट

सभी राज्यों के प्रतिनिधियों/नामितियों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	सभी राज्यों के प्रतिनिधि	बैठकों के आयोजन का समय अंतराल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	मुख्य सचिव और विशेष मुख्य सचिव (आर एवं बी), आंध्र प्रदेश सरकार नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रहे हैं	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
2.	अरुणाचल प्रदेश	कोई विशिष्ट नामन नहीं परन्तु मामले को हल करने के लिए निरन्तर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं	कोई परियोजना नहीं।
3.	असम	मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा बैठकें की जाती हैं और विभिन्न स्तरों पर समन्वय बैठकें की जाती हैं।	एक से तीन माहा।
4.	बिहार	सचिव (परिवहन)	दो माह में एक बार अथवा जरूरत पड़ने पर।

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग को समीक्षा बैठक हेतु मनोनीत किया गया है।	दो माह में एक बार।
6.	गोवा	राजस्व सचिव, गोवा सरकार	दो माह में एक बार।
7.	गुजरात	मुख्य इंजीनियर (एन.एच.) एवं अपर सचिव, सड़क एवं भवन	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
8.	हरियाणा	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (बी एवं आर), हरियाणा सरकार	एक से तीन माह।
9.	हिमाचल प्रदेश	सदस्य, योजना, हिमाचल प्रदेश	एक से तीन माह।
10.	जम्मू और कश्मीर	मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं।	एक से तीन माह।
11.	झारखंड	सचिव (परिवहन)	माह में एक बार।
12.	कर्णाटक	अपर मुख्य सचिव, अवसंरचना विकास विभाग (आईडीडी)	दो से तीन माह।
13.	केरल	मुख्य सचिव, केरल नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रहे हैं	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
14.	मध्य प्रदेश	प्रधान सचिव (परिवहन)	त्रैमासिक और जरूरत पड़ने पर।
15.	महाराष्ट्र	मुख्य सचिव, महाराष्ट्र द्वारा समीक्षा बैठकें की जाती हैं जिसमें ओएसडी/रेलवे और अन्य अधिकारी सहायता करते हैं	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
16.	मणिपुर	परिवहन सचिव, नागालैण्ड सरकार	एक से तीन माह।
17.	मेघालय	अपर मुख्य सचिव, मेघालय	दो माह में एक बार।
18.	मिज़ोरम	सलाहकार रेलवे समन्वय	त्रैमासिक।
19.	नागालैण्ड	मुख्य सचिव, नागालैण्ड सरकार की अध्यक्षता में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु राज्य समन्वय समिति	त्रैमासिक।
20.	ओडिशा	आयुक्त, रेल समन्वय सह विशेष सचिव, वाणिज्य एवं परिवहन (टी) विभाग, ओडिशा सरकार	त्रैमासिक या जरूरत पड़ने पर।

1	2	3	4
21.	पंजाब	मुख्य इंजीनियर/लोक निर्माण विभाग (बी एवं आर)/ पंजाब सरकार	एक से तीन माह।
22.	राजस्थान	मुख्य सचिव (लोक निर्माण विभाग)- उत्तर पश्चिम रेलवे अपर आयुक्त (रेलवे समन्वय)- पश्चिम मध्य रेलवे	माह में एक बार।
23.	सिक्किम	मुख्य सचिव, सिक्किम	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
24.	तमिलनाडु	प्रधान सचिव (परिवहन)। मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा बैठकें की जाती हैं।	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
25.	तेलंगाना	सचिव (परिवहन)। मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा बैठकें की जाती हैं।	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
26.	त्रिपुरा	परिवहन सचिव, त्रिपुरा सरकार	एक से तीन माह।
27.	उत्तर प्रदेश	प्रधान सचिव (परिवहन) बैठकों में समन्वय करते हैं।	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।
28.	उत्तराखंड	सचिव, परिवहन, उत्तराखंड सरकार	एक से तीन माह।
29.	पश्चिमी बंगाल	सचिव (परिवहन)	आपसी सहमति से आवधिक रूप से निर्धारित।

Monitoring of railway projects by State representatives

†*321. SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether representatives from States are appointed to monitor the railway projects running in their respective States;

(b) if so, the details of States whose representatives have not been appointed at present and by when such appointments would be made; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. To expedite the Railway Projects and to improve coordination with State Government for faster execution, Ministry of Railways had requested the State Governments for nomination of representatives of the States. Majority of the States have nominated their representatives to sort out different issues of mutual coordination and to monitor progress of Railway Projects in their respective State.

Details of the representatives/nominee of all States are given in Annexure (*See* below). The representative/nominee from States have been holding regular meetings with railway authorities on various issues involving alignment, land acquisition, forestry and wild life clearances, law and order problems, Road Over and Under Bridges, shifting of electrical lines, canal crossings, funding of projects, identification of interested parties etc.

To strengthen the coordination mechanism, Nodal Officers have also been nominated from Zonal Railways for each State with a defined role of identifying the projects, requiring coordination with State Government and arranging meetings of Railway Officials with the State Government.

In order to streamline information flow during meetings with dignitaries in Ministry of Railways, Nodal Officers in Railway Board for each State/UT have also been nominated to keep the updated status of various Railway related demands and monitoring the progress of various projects and issues.

Annexure

Details of the representatives/nominee of all States

Sl. No.	Name of the State	Representative of State	Periodicity of meetings
1.	Andhra Pradesh	Chief Secretary and Special Chief Secretary (R&B), Govt. of Andhra Pradesh are holding regular meetings.	Fixed periodically with mutual consent.
2.	Arunachal Pradesh	No specific nomination but frequent coordination meetings are held to resolve the issue.	No project

Sl. No.	Name of the State	Representative of State	Periodicity of meetings
3.	Assam	Review Meetings are taken by Chief Secy & Coordination meetings done at different levels	One to Three months.
4.	Bihar	Secretary(Transport)	Once in two months or need based.
5.	Chhattisgarh	Secretary, Commerce & Industry is nominated Review meeting by Chief Secretary, Chhattisgarh	Once in two months.
6.	Goa	Revenue Secretary, Govt, of Goa	Once in two months.
7.	Gujarat	Chief Engineer(N.H) & Addl. Secy. Road & Buildings	Fixed periodically with mutual consent.
8.	Haryana	Chief Engineer, Public Works Department (B&R), Govt, of Haryana	One to Three months.
9.	Himachal Pradesh	Member, Planning, Himachal Pradesh Govt.	One to Three months.
10.	Jammu and Kashmir	Meetings are held by Chief Secretary, J&K	One to Three months.
11.	Jharkhand	Secretary (Transport)	Once in a Month.
12.	Karnataka	Addl. Chief Secretary, Infrastructure Development Department (IDD)	Two to three months.
13.	Kerala	Chief Secretary, Kerala is holding regular meetings	Fixed periodically with mutual consent.
14.	Madhya Pradesh	Principal Secretary (Transport)	Quarterly & need based.
15.	Maharashtra	Review meetings by Chief Secretary, Maharashtra, assisted by OSD/Rlys and other officers	Fixed periodically with mutual consent.

Sl. No.	Name of the State	Representative of State	Periodicity of meetings
16.	Manipur	Transport Secretary, Govt. of Nagaland	One to Three months.
17.	Meghalaya	Addl. Chief Secretary, Meghalaya	Once in two months.
18.	Mizoram	Advisor Rly. Coordination,	Quarterly
19.	Nagaland	State Coordination Committee for Infrastructure projects headed by Chief Secretary, Government of Nagaland	Quarterly
20.	Odisha	Commissioner, Rail Coordination-cum-Special Secretary, Commerce & Transport(T) department, Govt, of Odisha	Quarterly or need based.
21.	Punjab	Chief Engineer/PWD(B&R)/ Punjab Govt.	One to Three months.
22.	Rajasthan	Principal Secretary (PWD)- NWR Addl. Commissioner (RIY. Coord.) - WCR	Once in a month.
23.	Sikkim	Chief Secretary, Sikkim	Fixed periodically with mutual consent.
24.	Tamil Nadu	Principal Secy. (Transport). Review meeting by Chief Secy.	Fixed periodically with mutual consent.
25.	Telangana	Secretary (Transport) Review meeting by Chief Secy.	Fixed periodically with mutual consent.
26.	Tripura	Transport Secretary, Govt. of Tripura	One to Three months.
27.	Uttar Pradesh	Principal Secy. (Transport) coordinates the meetings.	Fixed periodically with mutual consent.

Sl. No.	Name of the State	Representative of State	Periodicity of meetings
28.	Uttarakhand	Secretary, Transportation, Uttarakhand Govt.	One to Three months.
29.	West Bengal	Secretary (Transport)	Fixed periodically with mutual consent.

MR. CHAIRMAN: Question No. 321. Questioner is not present. Are there any supplementaries?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, Sir, the coordination between the State Governments and the Ministry of Railways is quite essential in the growing pattern of the transport facilities and the energy supply systems wherein, all across the country, the zonal meetings with the public representatives, in particular, with the Members of Parliament are not conducted properly, with agenda, and periodically. Even the involvement of the public representatives, in particular, MPs in specific zones is minimal. I would like to know from the Minister whether these nodal officers, either from the Railways or from the State Governments, would be involved and work in coordination with the public representatives so that the ground realities can be reflected. Thank you, Sir.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, as the hon. Member has pointed out, any Railway project that needs to be implemented has to be implemented in some State or the other. It cannot be implemented by Central Government somewhere in the air. Therefore, coordination with the State Government is very critical, very important. So, for the first time, we have decided to appoint a Nodal Officer in the Railway Board, in each zone, dealing with a particular State and requested all the State Governments also to appoint a Nodal Officer. This process has already been completed. In addition to this, what the hon. Member wants to know, I had announced, I, think, about one-and-a-half or two years ago, that we would create a committee at division level, zonal level, which will be chaired by hon. Member of Parliament, thus including Members of Parliament. If you have chosen a particular place, you will be part of that. Now, that is one process. But, of course, these Nodal Officers in the Railway Board, if you want to approach them, you are most welcome to approach them. In fact, I have already directed them that any Member of Parliament making any request will be attended to by this particular Nodal Officer in the Railway Board itself.

श्री हरिवंशः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई राज्यों के साथ रेलवे ने मिलकर दशकों वर्ष पहले ज्वाइंट में प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसमें एक-तिहाई पैसा केन्द्र को और दो-तिहाई पैसा राज्यों को लगाना था। ऐसे कुल कितने प्रोजेक्ट्स कितने वर्षों से चल रहे हैं, कितने राज्यों के साथ चल रहे हैं, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हुए हैं और समय से पूरे न होने के कारण उन प्रोजेक्ट्स का cost escalation कितना हुआ है?

श्री सुरेश प्रभुः सर, वैसे तो यह जो सवाल आपने पूछा है, यह इससे संबंधित नहीं है। फिर भी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अनुमति दें। सर, यह जो व्यवस्था थी कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर cost-sharing basis पर प्रोजेक्ट्स लगायेंगे, इसमें मूलतः यह जो कमी थी, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि यदि हम लोगों ने आज तय किया कि एक सौ करोड़ का प्रोजेक्ट implement करना है, राज्य सरकार 50 करोड़ रुपए देने को राजी हो गयी और शायद उसने जमा भी कर दिया। यदि प्रोजेक्ट का cost time overrun हो जाता है, तो राज्य सरकार कहेगी कि हमने तो अपना पैसा दे दिया था, अब क्यों हमसे दोबारा पैसा मांग रहे हो। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। परन्तु किसी कारण से इस तरह की अव्यवस्था नहीं बने, हम लोगों ने उसके संबंध में एक बढ़िया व्यवस्था बनाई है, उसका नाम ज्वाइंट वेंचर विद स्टेट है। इसमें हम लोग 50 प्रतिशत ईक्विटी लेंगे और राज्य सरकार 50 प्रतिशत लेगी, उसमें ज्वाइंट ओनरशिप रहेगी, यह cost-sharing पर हम लोग cost दे रहे हैं और ओनरशिप सिर्फ रेलवे के पास ही है। रेलवे तय करेगी कि क्या करना है और राज्य सरकार का उसमें कोई say नहीं है। अभी हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, उस के अंतर्गत जो नयी कंपनी बनेगी, उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी रहेंगे। उस के लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे और वही तय करेंगे कि प्रोजेक्ट की priority क्या हो, किस तरह से implementation हो। सर, दूसरी व्यवस्था यह है कि जैसा मैंने कहा 50 करोड़ आप दीजिए, 50 करोड़ हम देंगे, यह व्यवस्था नहीं रहेगी। हम 25 करोड, 25 करोड़ दोनों मिलकर लगाएंगे क्योंकि यह equity है और balance amount का debt लेकर उस प्रोजेक्ट को implement करेंगे। उस से यह होगा कि priority राज्य सरकार तय करेगी, लोकल लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, Land acquisition के इश्यूज, forest clearance के इश्यूज और बहुत जगह लोकल गवर्नमेंट को clearance देनी होती है, बहुत जगह पर utilities shift करने की वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। इन सभी कारणों से प्रोजेक्ट निर्धारित समय में पूरे नहीं किए जा सकते। इन सभी कारणों को दूर कर के नई व्यवस्था का स्वागत सभी राज्यों ने किया है। सर, 17 राज्यों ने तो in principle agreement किया था और कुछ राज्य बहुत आगे बढ़े हैं। उस में हमारे राजा जी को जानकर खुशी होगी कि उन राज्यों में केरल राज्य भी है। हम ने इस तरह की व्यवस्था की है और हम चाहते हैं कि यह नयी व्यवस्था लागू हो। अभी आपने कहा कि कितनी cost होगी, यह बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हमने इस कमी को देर कर के नयी व्यवस्था बनायी है। इस के बारे में cost-sharing के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें मैं आप की अनुमति से टेबल पर रख दूंगा। वह जानकारी आप को मिल जाएगी।

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी

तक कितने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इन की बैठक हुई है और उस बारे में रिपोर्ट कितने राज्यों से आयी है?

श्री सुरेश प्रभुः सर, मैं खुद सभी राज्यों में गया हूं और एक ही बार नहीं कई बार गया हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप पहले दिन ओडिशा में थे। हमारे दलवई साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कितनी बार गए? हम ने सभी राज्यों में जाकर वहां के प्रतिनिधियों से मिलकर और वहां के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक कर के बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की है। सर, यह व्यवस्था तो political level पर हो गयी, administrative level पर, institutionalized manner में जो व्यवस्था की है, उस में राज्य सरकारों के बारे में जानकारी, मैंने इस body of Answer में ही पूरी जानकारी दी है। साथ ही रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उन की जानकारी भी मैं circulate कर दूंगा, जिस से आप को भी पता चलेगा कि मेरे राज्य के प्रतिनिधि कौन हैं। आप उन के साथ सीधे interact कर सकते हैं। सर, तीसरी बात, हमारे जोन में भी हम ने हमारे ऑफिसस बनाए हैं, जो राज्य सरकार के साथ ही coordinate करेंगे on one hand और रेलवे बोर्ड में भी उन का coordination रहेगा।

Decline in population of livestock

*322.SHRI MOHD. ALI KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a significant decrease of livestock over the years, if so, the details thereof; and

(b) whether a livestock census has been conducted recenuy, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There has been a very small decrease of only about 3.33% in the total Livestock population between Livestock Census, 2007 and Livestock Census, 2012.

(b) The Livestock Census is conducted once in every five yea` The latest Livestock Census has been conducted during the year 2012 in participation with all States and Union Territories. The livestock species namely Cattle, Buffaloes, Sheep, Pigs, Horses & Ponies, Mules, Donkeys, Camels, Mithun and Yak have been included in the Census. Poultry population has also been covered in the Livestock Census-2012. The key findings in respect of some of the major species of livestock is given below: